सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹02

# स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, बुधवार, 09 जुलाई, 2025
वर्षः 02, अंकः 185, पृष्ठः 8+4

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पौधरोपण महाअभियान का किया शुभारंभ

» Pg 09

**इनसाइड** जनशिकायतों के निस्तारण में झांसी रेंज अव्वल... » Pg 03

## सस्पेंशन निरस्त होते ही ज्वाइन करने पहुंचे हरिदत्त नेमी

# सीएमओ कार्यालय में तूतू-मैंमैं...

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

» पूर्व सीएमओ का दखल, कुर्सी पर बैठने का मामला तूल पकड़ा, एफआईआर की तैयारी में जिला प्रशासन

» हाईकोर्ट से राहत के बाद भी जबरन दफ्तर में घुसने पर उठे सवाल, कानूनी राय ले रहा जिला प्रशासन

**कानपुर।** कांशीराम स्वास्थ्य भवन स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में पूर्व सीएमओ डॉ. हरि दत्त नेमी के अचानक पहुंचकर सरकारी कुर्सी पर बैठ जाने का मामला अब गंभीर मोड़ ले चुका है। इस घटना को लेकर प्रशासन विधिक पहलुओं पर मंथन कर रहा है, और जल्द ही उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज हो सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, हाईकोर्ट ने जरूर उनके निलंबन पर अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दोबारा कार्यभार ग्रहण करने की कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली थी। नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति अथवा बहाली का अधिकार केवल विभागीय उच्चाधिकारियों या शासन के पास होता है। अदालत से स्टे मिलना नियुक्ति का आदेश नहीं होता।

**बिना अनुमति पहुंचे ऑफिस, बैठ गए कुर्सी पर :** डॉ. हरि दत्त नेमी सोमवार को अचानक कांशीराम स्वास्थ्य भवन पहुंचे और वर्तमान सीएमओ डॉ. डॉ. उदय नाथ को हटाकर खुद कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपने वापस कार्यभार संभालने की बात कही और मौजूदा व्यवस्था को नकार दिया। इस घटनाक्रम से स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन में भी हड़कंप मच गया।

> कानूनी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति अथवा बहाली का अधिकार केवल विभागीय उच्चाधिकारियों या शासन के पास होता है। अदालत से स्टे मिलना नियुक्ति का आदेश नहीं होता।

सूत्रों की मानें तो वर्तमान सीएमओ को न हटाया गया है, न ही कोई तबादला आदेश जारी हुआ है। ऐसे में पूर्व अधिकारी द्वारा खुद को पुनः तैनात कर लेना और कार्यालय संचालन का प्रयास न केवल अनुशासनहीनता बल्कि कानूनी उल्लंघन भी माना जा रहा है।

# प्रशासन ले रहा विधिक राय, हो सकती है एफआईआर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**कानपुर।** जिला प्रशासन इस प्रकरण की कानूनी समीक्षा कर रहा है। कानूनी जानकारों की राय ली जा रही है कि क्या यह कृत्य सरकारी कार्य में बाधा, अनधिकृत प्रवेश और सेवा नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। संभावना जताई जा रही है कि डॉ. नेमी के खिलाद्वक्त आईपीसी की धारा 186 (सरकारी कार्य में बाधा) व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उच्चाधिकारियों का कहना है कि अगर किसी को न्यायालय से राहत मिलती है तो उसे विधिवत ज्वाइनिंग आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, न कि प्रशासनिक प्रक्रिया को दरकिनार कर सीधे दफ्तर में जाकर कब्जा जमाना चाहिए।

## स्वास्थ्य विभाग में खलबली, कर्मचारी असमंजस में

इस घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मियों में असमंजस की स्थिति है। एक ही कुर्सी पर दो अधिकारियों के दावे ने कार्य प्रणाली को प्रभावित किया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या अंतिम निर्णय लेता है और किसके आदेश को वैध माना जाता है। फिलहाल डॉ. उदय नाथ ही सीएमओ बने रहेंगे जब तक शासन से स्पष्ट निर्देश नहीं आता। वहीं,पूर्व सीएमओ द्वारा सीधे कुर्सी पर बैठ जाना अब खुद उनके लिए मुश्किल का कारण बनता जा रहा है। यदि इस पर जल्द रोक नहीं लगी तो यह प्रकरण न केवल कानूनी कार्रवाई का रूप ले सकता है, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन पर भी गहरा सवाल खड़ा करेगा।

# यूपी में 22 पीसीएस अफसरों का हुआ प्रमोशन, आईएएस बने

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

**यूपी के पीसीएस को आईएएस काडर में पदोन्नति, नियुक्ति विभाग ने जारी किया आदेश**

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश के 22 पीसीएस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) काडर में पदोन्नति दे दी गई है। केंद्रीय कामिज्क एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना के क्रम में इस संबंध में उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

प्रमोशन मिलने के बाद आईएएस बने पीसीएस पीसीएस भानु प्रताप यादव, राजेश कुमार सिंह, बलराम सिंह, शैलेंद्र कुमार भाटिया, देवी प्रसाद पाल, अंजू लता, जय नाथ यादव, राम सुरेश वर्मा, रणविजय सिंह, दयानंद प्रसाद, विनोद कुमार गौड़, सचिन कुमार सिंह, विवेक कुमार श्रीवास्तव, बसंत अग्रवाल, वंदिता श्रीवास्तव, महेंद्र कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, राजेश कुमार, योगेंद्र कुमार, नीलम, विधान जायसवाल आईएएस बन गए।

# दरोगा को बदनाम करने की गैंगवार स्क्रिप्ट लीक

» वर्दी पर हमला, साजिश का खुलासा दरोगा को फंसाने के पीछे ब्लैकमेलिंग गैंग का हाथ

» तथाकथित पत्रकारों का फर्जीवाड़ा बेनकाब, दरोगा प्रवास शर्मा को किया था टारगेट

» मुखारबिंद से फूटा सच फर्जी पत्रकारों के इशारे पर दरोगा पर लगाया था झूठा आरोप

**प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया**

कानपुर। बीते दिनों कानपुर में एक ईमानदार दरोगा को शर्मनाक साजिश का शिकार बनाया गया था। किदवई नगर चौकी इंचार्ज दरोगा प्रवास शर्मा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने खुद को मध्य प्रदेश क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर एक युवक का अपहरण किया और उससे मोटी रकम वसूली। सोशल मीडिया पर इन आरोपों को तेजी से फैलाया गया जिसके चलते पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई। परंतु अब इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है और जो सच सामने आया है, वह चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि पत्रकारिता की आड़ में पनप रहे अपराध का भंडाफोड़ भी है।

दरअसल, खुद वही युवक जिसने दरोगा पर ये संगीन आरोप लगाए थे, अब मुखारबिंद से कबूल कर रहा है कि उसे ऐसा करने के

प्रवास शर्मा चौकी इंचार्ज किदवई नगर

लिए कुछ तथाकथित पत्रकारों ने बरगलाया था। युवक ने यह भी बताया कि उसके द्वारा की गई शिकायतें झूठी थीं और उसे इस्तेमाल किया गया था ताकि दरोगा प्रवास शर्मा को बदनाम कर सस्पेंड कराया जा सके। यह घटना न केवल कानपुर पुलिस की कार्यशैली

पर सवाल उठाने वाली थी, बल्कि अब यह सवाल उठाने लगी है कि आखिर पत्रकार की पहचान के पीछे छिपकर ये कौन लोग हैं जो वर्दीधारी अफसरों को झूठ के जाल में फंसाने की साजिश रचते हैं।

**साफ सुथरी वर्दी पर फेंकी गई साजिश की स्याही**

दरोगा प्रवास शर्मा का रिकॉर्ड साफ रहा है। जिस भी चौकी पर उनकी तैनाती हुई, उन्होंने देह व्यापार, मादक पदार्थों की तस्करी, और अन्य अवैध धंधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। यही कारण है कि उन्हें किदवई नगर जैसे वीआईपी और संवेदनशील इलाके की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहाँ कई विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और संभ्रांत नागरिकों के आवास स्थित हैं। परंतु इसी इलाके में स्थित है एक सक्रिय आपराधिक गैंग, जिसने पत्रकारिता की आड़ में जिस्मफरोशी, ब्लैकमेलिंग और फर्जी मुकदमों का धंधा चला रखा है दरोगा के द्वारा की गई सख़्त कार्यवाहियों से घबराकर यही गैंग दरोगा प्रवास शर्मा के खिलाफ साजिश रचने में जुट गया।

**फर्जी पत्रकारिता के पीछे छिपे गंदे कारोबारियों का भंडाफोड़**

हालिया घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि पत्रकारिता का चोला ओढ़कर कुछ अनैतिक तत्व शहर में अपराध की समानांतर व्यवस्था चला रहे हैं।

सोशल मीडिया पर दरोगा प्रवास शर्मा के खिलाफ चलाए गए बदनाम करने के अभियान के पीछे भी इन्हीं तत्वों का हाथ बताया जा रहा है। युवक के खुलासे के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पुलिस के ईमानदार अफसरों को टारगेट कर इन तथाकथित पत्रकारों ने न केवल अपने संस्थानों को बदनाम किया है बल्कि आमजन के विश्वास को भी चोट पहुंचाई है। ऐसे गिरोह के खिलाफ पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को जमीनी स्तर पर जांच कराकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे असल पत्रकारिता की गरिमा और जनता का विश्वास दोनों सुरक्षित रह सके।

# झोला छीनकर भागे शातिर युवक 24 घंटे में पुलिस के शिकंजे में

» महिला से छीना गया था झोला जिसमे थी मोबाइल और नकदी

» पुलिस की सक्रियता से चंद घंटों में हुआ खुलासा

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

बिल्हौर (कानपुर)। महिला से झोला और मोबाइल फोन छीनकर भागने वाले दो शातिर युवकों को बिल्हौर पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाल अशोक कुमार सरोज ने एक टीम गठित कर तफ्तीश शुरू करवाई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला अपने कार्य से जा रही थी, तभी दो युवकों ने झपट्टा मारते हुए झोला छीन लिया। झोले में एक मोबाइल फोन और करीब 440 रुपये नकद थे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।जांच के दौरान मिले सुरागों और मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बिल्हौर के नानामऊ अंडरपास के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान राजा पुत्र सोनेलाल निवासी बाल्मीकि नगर कस्बा और शिवम यादव पुत्र स्व. गुलाब सिंह निवासी वैष्णो नगर कस्बा बिल्हौर के रूप में हुई है।

गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से पीड़िता का मोबाइल, आधार कार्ड और पर्स बरामद हुआ। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब उनके आपराधिक इतिहास की भी पड़ताल कर रही है।

# जनशिकायतों के निस्तारण में झांसी रेंज अव्वल

**» लगातार चौथी बार हासिल किया प्रदेश में पहला स्थान**

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

झांसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित जनसुनवाई समन्वय प्रणाली (आईजीआरएस) की जून माह की मूल्यांकन रिपोर्ट में झांसी रेंज ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है।

झांसी रेंज की पुलिस ने जनशिकायतों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लगातार चौथी बार प्रदेश के सभी परिक्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

## ललितपुर जनपद ने भी मारी बाजी, डीआईजी केशव कुमार चौधरी ने दी टीम को बधाई

इस उपलब्धि की जानकारी झांसी रेंज के कर्तव्यनिष्ठ, न्यायप्रिय एवं ईमानदार छवि के डीआईजी केशव कुमार चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई पोर्टल, आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा शासन स्तर पर प्रत्येक माह की जाती है, और प्राप्त फीडबैक के आधार पर रैंकिंग जारी होती है।इस रैंकिंग में रेंज के ललितपुर जनपद ने भी पूरे उत्तर प्रदेश में जनपदों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। डीआईजी चौधरी ने कहा कि शिकायतों का विधिक निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप प्राथमिकता से किया जाना चाहिए ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वयं मौके पर जाकर शिकायतों का स्थलीय निरीक्षण करें और निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करें।इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईजीआरएस सेल प्रभारी उपनिरीक्षक राजेश सिंह और उनकी टीम को डीआईजी द्वारा नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही टीम को भविष्य में भी इसी मेहनत, निष्ठा और तत्परता के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

यह सफलता झांसी रेंज पुलिस की पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाती है।

**पुनः वापसी**

**कानपुर डीएम-सीएमओ प्रकरण**

# डॉ. हरिदत्त नेमी ने दोबारा लिया चार्ज

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

कानपुर। डॉ. हरिदत्त नेमी ने आकर दोबारा जॉइन कर लिया। सीएमओ ने बताया कि डीएम ने हटाने के लिए फोर्स भेजी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने सीएमओ के निलंबन पर रोक लगा दी है।कानपुर के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिनका विवाद जिलाधिकारी से हुआ था, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी अपने कार्यालय में चार्ज लेने पहुंचे।

## कोर्ट ने आदेशों पर लगाई है रोक, पुलिस बल तैनात

**19 जून को कर दिया था निलंबित**

डॉ. नेमी की राज्य सरकार ने डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से विवाद के बाद बीती 19 जून को निलंबित कर दिया था। याची ने खुद को निलंबित करने समेत श्रावस्ती के अतिरिक्त सीएमओ डॉ. उदय नाथ को कानपुर नगर का सीएमओ तैनात करने के आदेशों को चुनौती दी है।

**18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई**

याची के अधिवक्ता एलपी मिश्र का कहना था कि बगैर कोई जांच की कारवाई शुरू किए याची को निलंबित किया गया। साथ ही, निलंबन आदेश में जो आरोप लगाए गए हैं, वे परिणामी बड़ी सजा वाले नहीं होंगे। ऐसे में, नियमानुसार याची का निलंबन नहीं किया जा सकता था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को नियत की है।

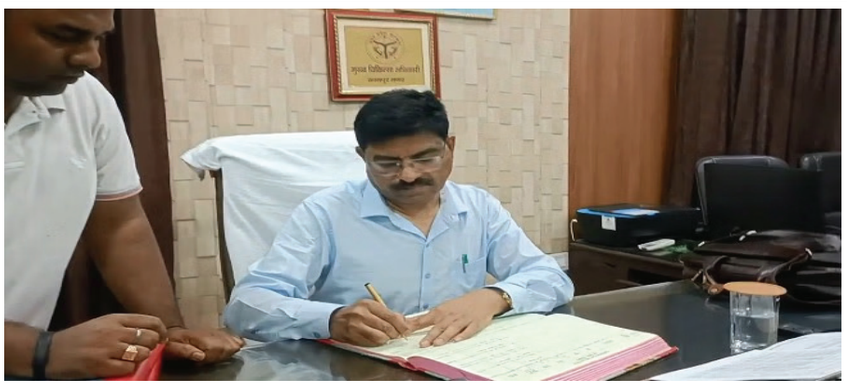

मौके पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस बल मौजूद है।बता दें कि कल ही हाईकोर्ट ने सीएमओ के निलंबन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए सीएमओ की तैनाती आदेश पर भी रोक लगाई है। अदालत ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कर हफ्ते का समय दिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश डॉ. नेमी की याचिका पर दिया।

# कांग्रेस ग्रामीण की नई कार्यकारिणी का ऐतिहासिक समारोह

**» जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में बढ़ रहा कारवां**

## तिलक हॉल में जुटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, वरिष्ठ नेताओं का हुआ जमावड़ा

**प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया**

कानपुर। जिला कांग्रेस कमेटी नगर ग्रामीण की नई कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण समारोह में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। तिलक हॉल में आयोजित इस समारोह में लंबे अरसे बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। कार्यक्रम में जिलेभर के विभिन्न ब्लॉकों और विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता जिला कांग्रेस नगर ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने की, जबकि मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुरेन्द्र सिंह ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित किए।

पदभार ग्रहण से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुरेन्द्र सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, फ्देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। आंकड़ों के खेल से जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि बेरोजगारी और गरीबी चरम पर है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना यह दर्शाता है कि सरकार की नीतियां विफल हैं। उन्होंने मोदी सरकार को झूठ की नींव पर खड़ी सरकार बताया।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा, फ्हमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। 2027 के चुनाव में हर कांग्रेस कार्यकर्ता को 'राहुल गांधी के बब्बर शेर' की तरह हर बूथ पर सक्रिय होना होगा।पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्रा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा, यह दायित्व कांटों भरा ताज है, जिसे निभाकर साबित करना होगा कि संगठन ने सही चुनाव किया है।वरिष्ठ कांग्रेस नेता हर प्रकाश अग्निहोत्री ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसियों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील की और कहा, अब मिशन 2027 को लक्ष्य बनाकर काम करना है और सरकार बनाकर ही चैन लेना है।कार्यक्रम का संचालन धवल पांडेय और जय शंकर द्विवेदी ने किया, जबकि आभार ज्ञापन शक्ति पांडेय एडवोकेट ने किया।इस मौके पर कृपेश त्रिपाठी, आनंद मेहरोत्रा, उषा रानी कोरी, अमित पांडेय, महेश दुबे टंडन, उमेश दीक्षित, विकास अवस्थी, आनंद वर्मा, राजीव द्विवेदी, तुफैल खान, शशिकांत दीक्षित, निज़ामुद्दीन खान, शिव किशोर मिश्रा, बृजेश त्रिपाठी, प्रकाश मिश्रा, राजेन्द्र बाल्मीकि, प्रदीप द्विवेदी, अंकित कन्नौजिया, संदीप मिश्रा, अमित पटेल, पं. श्रीकांत शर्मा, विपुल अवस्थी, शिवम मालवीय, आकर्षण तिवारी, आलोक तिवारी, हाजी वसीक सहित कई प्रमुख कांग्रेसजन मौजूद रहे।

# कानपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, चमनगंज में अवैध निर्माण सील

## प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने मौके पर पहुंचकर की त्वरित कार्रवाई

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) द्वारा अवैध निर्माणों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल के निर्देश पर सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने थाना बजरिया क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मोहम्मद अली पार्क के पास, परिसर संख्या 88/91 चमनगंज में चल रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया। केडीए के अनुसार मोहम्मद अजीज व अन्य द्वारा किए जा रहे

इस अवैध निर्माण की सूचना पर केडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवाया और भवन को सील बंद किया।प्राधिकरण ने साफ किया है कि बिना स्वीकृति नक्शा एवं अनुमति के किए जा रहे निर्माणों पर भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। केडीए प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

यह अभियान कानपुर नगर को सुव्यवस्थित और अवैध निर्माणों से मुक्त करने की दिशा में एक और अहम कदम है।

## सम्पादकीय

# कमियां दूर कर लाभ का हो विस्तार

इसमें दो राय नहीं कि पिछले एक दशक में प्रौद्योगिकी ने आम भारतीय के जीवन को सहज-सरल बनाने में निर्णायक भूमिका निभायी है। आज तमाम तरह की सुविधाओं को हासिल करने के लिये उसे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अनेक सेवाएं एक क्लिक के साथ उसकी मुट्ठी में होती हैं। दरअसल, डिजिटल इंडिया की महत्वाकांक्षी पहल नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। जिसका मकसद रोजाना व्यवहार में सामने आने वाली जटिलताओं को दूर करके जीवन को आसान बनाना था। निस्संदेह, पिछले एक दशक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने कई प्रकार से नागरिकों को सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभायी है। विशेष रूप से डिजिटल भुगतान आज पूरे देश में अपरिहार्य हो गए हैं। इससे जुड़े आंकड़े पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। इस वर्ष अप्रैल में लगभग 25 लाख करोड़ रुपये के यूपीआई लेन-देन किए गए हैं।

इन यूपीआई लेनदेन की संख्या करीब 1,860 थी। वर्ष 2023 में भारत ने वैश्विक रीयल-टाइम लेनदेन का 49 फीसदी हासिल किया। जिसमें 46 करोड़ लोग और 6.5 करोड़ व्यापारी यूपीआई का उपयोग कर रहे थे। निस्संदेह, शासन के विभिन्न क्षेत्रों में भी डिजिटल उपयोग में खासी प्रगति हुई है। जिससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी और नागरिकों के हितों के अनुकूल हो गई है। इस डिजिटल क्रांति के चलते स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच आसान हुई है। डिजिटल क्रांति से जुड़ी तमाम चुनौतियों के अलावा अभी देश में डिजिटल डिवाइड की समस्या बनी हुई है। जिसे यथाशीघ्र पाटने की जरूरत है। हालांकि, इस दिशा में आशातीत प्रगति भी हुई है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने के लिये चरणबद्ध प्रयासों की सख्त जरूरत है। यह चुनौती ग्रामीण भारत में अधिक नजर आती है। जहां इंटरनेट सेवाओं और मोबाइलों की पहुंच शहरों के मुकाबले कम है। जाहिर है, जब देश के हर व्यक्ति तक डिजिटल क्रांति का लाभ पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा, इस क्रांति के लक्ष्य अधूरे ही रहेंगे।

निश्चित रूप से देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग आदि सेवाओं में जो व्यापक सुधार आया है, उसका लाभ हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर देश में डिजिटल डिवाइड की खाई को पाटने की दिशा में मिशन के रूप में प्रयास जारी हैं। लेकिन हाल में हुए कुछ सर्वेक्षणों के निष्कर्ष चिंता बढ़ाने वाले हैं। इसमें शामिल व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण - दूरसंचार, 2025 का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के केवल 57.2 फीसदी स्कूलों में कार्यात्मक कंप्यूटर ही उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर 53.9 प्रतिशत स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। देश के विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत नेट परियोजना के तहत कुल 6.55 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिये लक्षित किया जाना था, लेकिन अभी तक उसमें दो-तिहाई गांवों को कवर किया जाना अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर देश की इस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने बीएसएनएल की दुर्दशा को भी उजागर किया है, जो एक के बाद एक पुनरुद्धार पैकेज मिलने के बावजूद टेलीकॉम क्षेत्र की निजी कंपनियों के खिलाड़ियों से पीछे है। निस्संदेह, मोदी सरकार के पास डिजिटल इंडिया की प्रगति के लिये अपनी पीठ थपथपाने के लिये कई कारण हैं, लेकिन उसे कमियों और अंतरालों पर ध्यान देने की सलाह दी जाएगी। निश्चित रूप से डिजिटल पारिस्थितिकीय तंत्र के भीतर व्याप्त असमानताओं को दूर किए बिना विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करना है।

# बड़े धार्मिक आयोजनों का वैज्ञानिक प्रबंधन जरूरी

विश्वनाथ सचदेव

**त्रिभाषा फार्मूले का विरोध करने वालों को भी यह समझना होगा कि आवश्यकता इसके ईमानदार क्रियान्वयन की है। वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में इस फार्मूले को स्वीकारा गया था। तब यह कहा गया था कि तीसरी भाषा के रूप में उत्तर वाले दक्षिण की किसी भाषा को सीखेंगे और दक्षिण वाले उत्तर की भाषा हिंदी को। पर उत्तर वालों ने यहां ईमानदारी नहीं दिखाई। उन्होंने तीसरी भाषा के रूप में दक्षिण भारत की किसी भाषा के बजाय मुख्यत- संस्कृत को चुना।**

**आपातकाल में हमारे संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गये थे- पहला 'पंथ निरपेक्षता' और दूसरा समाजवाद। संविधान जब तैयार किया जा रहा था तब भी इन शब्दों की आवश्यकता की चर्चा हुई थी, पर तब हमारे संविधान निर्माताओं ने यह माना था कि यह दोनों विचार संविधान में अन्यत्र स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं, अतः इन्हें अलग से प्रस्तावना में जोड़ना आवश्यक नहीं है। जब आपातकाल के दौरान इन्हें जोड़ा गया तो तर्क यह दिया गया था कि यह दोनों विचार प्रमुखता के साथ रेखांकित होने चाहिए। संविधान के 42वें संशोधन से इसे रेखांकित कर दिया गया।**

बाद की जनता पार्टी की सरकार ने भी इस बात को मान लिया। पचास साल बाद यह विवाद फिर सिर उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को यह लग रहा है कि इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना से हटा कर अब अपनी विचारधारा को संविधान में शामिल किया जा सकता है। और यदि संख्या की दृष्टि से फिलहाल संविधान में प्रयुक्त संशोधन नहीं हो सकता तो भी देश में अपने विचार के समर्थन में वातावरण बनाने का यह अच्छा मौका है।

ऐसी ही एक कोशिश महाराष्ट्र में भी हो रही है- राज्य की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र की नयी शिक्षा-नीति को लागू करने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए यह निर्णय लिया था कि राज्य में त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाये। इस फार्मूले के अनुसार राज्य के स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को मराठी और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जानी थी। विपक्ष, विशेषकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को, सरकार के इस निर्णय का विरोध करके अपनी जमीन को मज़बूत करने

का अवसर दिखाई दिया। उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी इस निर्णय को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगी। लगभग दो दशक पहले बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर अपना स्वयं का राजनीतिक दल बनाने वाले उनके भतीजे राज ठाकरे को भी इस स्थिति में एक अवसर दिखाई दिया और उन्होंने भी घोषणा कर दी कि राज्य सरकार की ‘मराठी विरोधी नीति’ को लागू नहीं होने दिया जायेगा। कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी भी ठाकरे बंधुओं के आह्वान के साथ जुड़ गयीं। एक बार फिर राज्य में मराठी अस्मिता के नाम पर माहौल बनने लगा। स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि पहली से पांचवीं तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जायेगी, यदि बच्चे किसी अन्य भाषा को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए स्कूलों में इसकी व्यवस्था की जायेगी, बशर्ते किसी अन्य भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम से कम बीस हो। सरकार को लगा था कि इस घोषणा से स्थिति संभल जायेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठे) और राज ठाकरे की मनसे, दोनों किसी भी कीमत पर इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तय हुआ कि पांच जुलाई को राज्य का समूचा विपक्ष मराठी भाषा और मराठी अस्मिता की रक्षा के नाम पर केंद्र के निर्देश से काम करने वाली महाराष्ट्र सरकार के निर्णय के विरोध में आंदोलन करेगा।बाजी हाथ से निकलते देख कर राज्य सरकार ने हिंदी की पढ़ाई वाला अपना कदम वापस लेने का निर्णय किया। अब एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है जो राज्य के स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूले को लागू किये जाने के बारे में अध्ययन करके अपना सुझाव देगी।

# पहाड़ों की संवेदनशीलता को समझना भी जरूरी

## हिमाचल में जल-रौद्र

पंकज चतुर्वेदी

**गंभीरता से देखें तो इन आपदाओं को बुलाने में इन्सान की भूमिका भी कम नहीं है। दुनियाभर के शोध कह रहे थे कि हिमालय पर्वत जैसे युवा पहाड़ पर पानी को रोकने, जलाशय बनाने और सुरंगें बनाने के लिए विस्फोटक के इस्तेमाल के अंजाम अच्छे नहीं होंगे।**

**सुंदर, शांत, सुरम्य हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कुदरत ने रौद्र रूप धारण किया है। छोटे से राज्य का बड़ा हिस्सा अचानक आई तेज बरसात और जमीन खिसकने से त्रस्त है तो जहां आपदा आई नहीं वहां के लोग भी आशंका में जी रहे हैं। आषाढ़ में मानसून की पहली बौछार के साथ ही कई जिलों, विशेषकर कुल्लू और धर्मशाला में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इससे कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। कुल्लू और धर्मशाला जिलों में अनेक जगह बादल फटने की घटनाएं हुईं, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और अनेक लापता हैं। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कांगड़ा के खनियारा क्षेत्र में इंदिरा हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास प्लैश फ्लड में 20 मजदूर बह गए, जिनमें से कुछ के शव बरामद हुए हैं, बाकी की तलाश जारी है।**

कुल्लू की सेंज घाटी में तमाम पर्यटक फंसे हुए हैं। यहां बादल फटने से एक ही परिवार के तीन लोग बह गए। धर्मशाला-चतरो-गगल मार्ग और अपर शिमला क्षेत्र में त्यूणी-हाटकोटी मार्ग जैसे कई प्रमुख मार्ग भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी तो सावन-भादों आगे हैं। दुखद यह कि वैज्ञानिकों द्वारा इस बारे में दी गई ढेर सारी चेतावनियां फाइलों में बंद हैं। सरकारी महकमे अपने ढर्रे पर काम कर रहे हैं जबकि पहाड़ जलवायु परिवर्तन के विविध कुप्रभावों से ग्रस्त हैं।इसी साल 14-15 फ़रवरी को आईआईटी, बॉम्बे में सम्पन्न दूसरे इंडियन क्रायोस्फीयर मीट में आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिकों ने एक शोधपत्र प्रस्तुत कर बताया था कि हिमाचल राज्य का 45 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। 5.9 डिग्री और 16.4 डिग्री के बीच औसत ढलान वाले और 1,600 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र विशेष रूप से भूस्खलन और बाढ़ दोनों के लिए प्रवण हैं। इस बैठक में दुनियाभर के लगभग 80 ग्लेशियोलॉजिस्ट, शोधकर्ता और वैज्ञानिक शामिल हुए। इतनी स्पष्ट चेतावनी के बावजूद न समाज चेता और न ही सरकार।नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसरो द्वारा तैयार देश के भूस्खलन नक्शे में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों को बेहद संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। देश के कुल 147 ऐसे जिलों में संवेदनशीलता की दृष्टि से मंडी को 16वें स्थान पर रखा गया है। यह आंकड़ा और चेतावनी फाइल में सिसकती रह गई।

यही हाल शिमला का हुआ जिसका स्थान इस सूची में 61वें नम्बर पर दर्ज है। प्रदेश में 17,120 स्थान भूस्खलन संभावित क्षेत्र अंकित हैं, जिनमें से 675 बेहद संवेदनशील मूलभूत सुविधाओं और घनी आबादी के करीब हैं। भूस्खलन की दृष्टि से किन्नौर जिला को सबसे खतरनाक माना जाता है। बीते साल भी किन्नौर के बटसेरी और न्यूगलसरी में दो हादसों में ही 38 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद किन्नौर जिला में भूस्खलन को लेकर भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के विशेषज्ञों के साथ-साथ आईआईटी, मंडी व रुड़की के विशेषज्ञों ने अध्ययन किया है।हिमाचल सरकार की डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा प्रकाशित एक 'लैंडस्लाइड हैज़ार्ड रिस्क असेसमेंट' अध्ययन ने पाया कि बड़ी संख्या में हाइड्रोपावर स्थल पर धरती खिसकने का खतरा है। लगभग 10 ऐसे मेगा हाइड्रोपावर प्लांट, स्थल मध्यम और उच्च जोखिम वाले भूस्खलन क्षेत्रों में स्थित हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सर्वेक्षण कर भूस्खलन संभावित 675 स्थल चिन्हित किए हैं।

# सावन व कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट

**» डीसीपी दिनेश त्रिपाठी की अगुवाई में समीक्षा बैठक,सुरक्षा में नहीं होगी चूक**

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

बिल्हौर (कानपुर)।सावन मास में कांवड़ यात्रा की भीड़ और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने कमान खुद संभाल ली है। मंगलवार को उन्होंने थाना शिवराजपुर क्षेत्र के खेरेश्वर मंदिर परिसर में एक व्यापक समीक्षा बैठक कर सुरक्षा तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की।

डीसीपी ने बैठक में शामिल सभी लोगों से बात कर समस्याएं जानी इसके बाद खुद कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का गहन मूल्यांकन किया।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा श्रद्धालुओं की आस्था हमारे लिए सर्वोपरि है,लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। हर पहलू पर सतर्कता बरती जाएगी।इस दौरान एसडीएम बिल्हौर संजीव दीक्षित, एसीपी अमरनाथ,शिवराजपुर इंस्पेक्टर, ब्लॉक प्रमुख शुभम बाजपेई समेत क्षेत्र के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे।

**समिति से संवाद,शांति की अपील**

डीसीपी ने कांवड़ यात्रा समिति के सदस्यों से खुलकर संवाद किया और यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग की अपील की। उन्होंने अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देने की बात दोहराई।

**सरैया घाट पर सुरक्षा का जायजा**

पुलिस फ़ोर्स के साथ डीसीपी श्री त्रिपाठी ने शिवराजपुर क्षेत्र के सरैया गंगा घाट का भी दौरा किया और वहां की सुरक्षा तैयारियों की जांच की।

उन्होंने बैरीकेडिंग, पुलिस बल की तैनाती, बिजली आपूर्ति, यातायात नियंत्रण और पार्किंग व्यवस्था जैसे बिंदुओं पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा कि भीड़ नियंत्रण और इमरजेंसी रिस्पांस को लेकर कोई चूक नहीं होनी चाहिए।

# कानपुर में छात्रा सृष्टि ने डीएम को पहनाया श्रीराम पटका

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

कानपुर। जिले के गोपाल नगर निवासी मां गायत्री इंटर कॉलेज में कक्षा दो में पढ़ने वाली नन्ही सृष्टि मंगलवार को अपने माता-पिता के साथ जिलाधिकारी माननीय जितेंद्र प्रताप सिंह से मिलने पहुंची। सृष्टि ने जिलाधिकारी के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें श्रीराम का पटका पहनाकर सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की।

छोटी सृष्टि के इस स्नेह भरे gesture से डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह भी भावुक नजर आए। उन्होंने सृष्टि को आशीर्वाद देते हुए कहा, हमें तो आपका सम्मान करना चाहिए, आप हमें सम्मानित करने आई हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। डीएम ने सृष्टि को भी साल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उसका हौसला बढ़ाया।

इस दौरान जिलाधिकारी ने सृष्टि से टेबल पूछा तो उसने बताया कि उसे दस तक के पहाड़े आते हैं। डीएम ने उसे सात का पहाड़ा सुनाने को कहा, जिसे सृष्टि ने आत्मविश्वास से सुनाया। जिलाधिकारी ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह आगे भी खूब पढ़े-लिखे और परिवार व जिले का नाम रोशन करे।

इस मौके पर सृष्टि के माता-पिता ओम कुमारी और राजेश कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने जिलाधिकारी का आभार जताया कि उन्होंने उनकी बेटी को इतना मान-सम्मान दिया और आशीर्वाद दिया।

# महिला स्वावलंबन को नई उड़ान: हर ग्राम पंचायत में बनेंगे 10 नए समूह

**» मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम प्रधानों संग की अहम बैठक, दिए एक माह में लक्ष्य पूरे करने के निर्देश**

**शंकर सिंह स्वराज इंडिया**

कानपुर देहात। **जनपद में जहां 3.19 लाख पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारक, 32 हजार प्रधानमंत्री आवास लाभार्थी और 79 हजार सक्रिय जॉबकार्ड धारक हैं, वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह गठन की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन0 ने ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर महिला स्वावलंबन को तेज़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।**

विकास भवन सभागार में आयोजित इस विशेष बैठक में प्रत्येक विकासखंड से 10-10 ग्राम प्रधानों को बुलाया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे आगामी एक माह में अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 10-10 स्वयं सहायता समूह गठित कराएं। यह कार्य ग्रामीण आजीविका मिशन व पंचायती राज विभाग की समन्वित भागीदारी से पूरा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि समूहों से जुड़ने वाली महिलाओं को उनकी रुचि के अनुसार नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा बैंक लिंकेज के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार हेतु आवश्यक फंड भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। सीडीओ ने कहा कि समूह से जुड़ने पर महिलाओं में आत्मबल और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, जिससे उनका व्यक्तित्व भी सशक्त बनता है।

बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी, उपायुक्त स्वरोजगार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

# अब बढ़ेगी पनकी महंत की मुश्किलें?

» एसीपी चकेरी की जांच में थाना प्रभारी को क्लीनचिट

» यक्ष प्रश्न क्या अब कानपुर पुलिस करेगी महंतों पर कार्यवाही?

» जिस मुकदमे के आधार पर दान पात्रों के ताले खुले वह मुकदमा क्षेत्राधिकार के अभाव में अदालत ने वापस किया

» यक्ष प्रश्न क्या अब दान पात्रों पर फिर से लगेंगे ताले?

अपीलीय अदालत के आदेश में उभरे आलोच्य बिंदुओं पर अब होगा फिर से परीक्षण










**मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया**

कानपुर। एक तरफ पनकी के महंत का विवाद अदालत में चल रहा है तो दूसरी ओर पनकी महंतों द्वारा श्री जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले थाना प्रभारी पर लगाए गए अभद्रता के आरोप पुलिस जांच में असत्य पाए गए। पिछले दिनों एक अदालत के आदेश से इन महंतद्वय पर पनकी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान महंत कृष्णदास की एक वीडियो क्लिप में भाषा शैली से तमाम प्रबुद्ध सनातनी असहमति जता रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि यदि महंत ने असत्य आरोप लगाकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया तो क्या पुलिस इन महंतों पर कार्रवाई करेगी? स्वराज इंडिया से बातचीत में महंत कृष्णदास ने कहा है पुलिस है तिल का ताड़ बनाती है। पुलिस की नजर में हम गलत हैं पुलिस सही है। यह तो विभाग विभाग का मामला होता है। जो किया ठीक है, हनुमान जी देखेंगे।

स्वराज इंडिया की कल के अंक में छपी खबर में बताया गया था कि वर्तमान समय में महंत विवाद 2022 से पूर्व की स्थिति में पहुंच गया है। पनकी मंदिर में एक महंत पद विवादित है। यदि पुलिस जगन्नाथ रथ यात्रा के समय इन महंतों द्वारा असत्य आरोप लगाकर उत्पन्न की गई विषम परिस्थितियों को लेकर कार्रवाई करती है तो इन महंतों की मुश्किलें बढ़ना तय है।

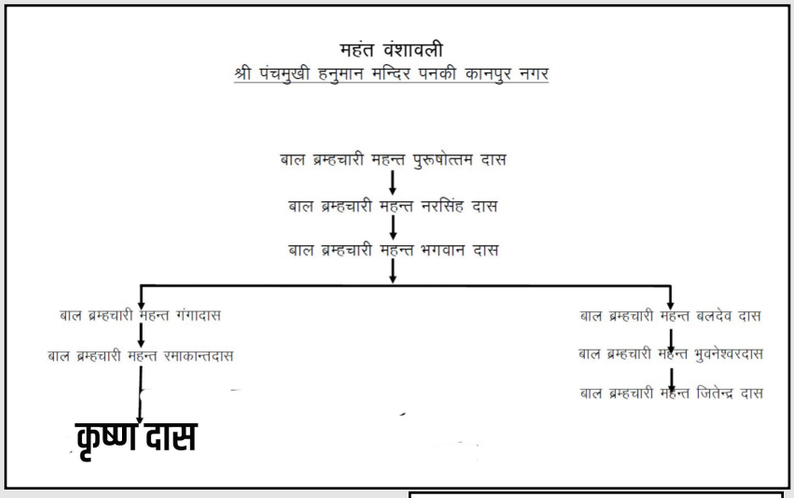

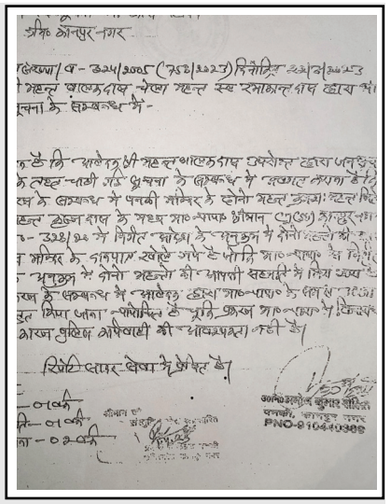

**पनकी मंदिर में कुप्रबंधन और अव्यवस्थाएं जारी**

सनातनियों की आस्था के प्रमुख केंद्र पनकी मंदिर में व्यवस्थाएं कुप्रबंधन का शिकार हैं। ?200 में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था से दर्शनार्थी कुपित हैं। सेवादारों की कमी के चलते हर मंगल और शनिवार को दर्शनार्थियों की लंबी लाइन मंदिर परिसर के बाहर तक पहुंच रही हैं और ऐसा लग रहा है महंतद्वय इन व्यवस्थाओं को सही कर पाने में अक्षम हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण मंदिर में सेवादारों की कमी होना है।

**कृष्ण दास एकमात्र महंत जो बाल ब्रह्मचारी भी नहीं हैं**

स्वराज इंडिया को प्राप्त इनपुट के अनुसार पनकी मंदिर महंत वंशावली में वर्तमान महंत कृष्णदास के अतिरिक्त सभी महंत बाल ब्रह्मचारी हैं। एडीजे 21 ने अपने आदेश में इस तथ्य का उल्लेख भी किया है।

साथ ही यह प्रश्न भी उठाया है कि उत्तराधिकारी घोषित होने की तिथि पर प्रतिवादी संख्या एक (कृष्ण दास) ने वैराग्य धारण कर लिया था या नहीं। अपीलीय न्यायालय के आदेश में यह भी प्रश्न उठाया गया है कि मात्र वसीयत द्वारा महंत जैसे पद को उत्तराधिकार में दिया जा सकता है या नहीं, इस बिंदु पर लोअर कोर्ट ने विचार नहीं किया है।

**आरटीआई में पनकी पुलिस ने बताया न्यायालय के आदेश से खुले दान पात्र के ताले**

महंत पद के दावेदार बालक दास को आरटीआई कानून के तहत मांगी गई सूचना पर वर्ष 2023 में पनकी पुलिस ने सूचना दी थी कि वाद संख्या 328/20 में निर्गत आदेश के अनुक्रम में दोनों महंतों की सहमति से दान पात्र के ताले खोले गए हैं। यह वही मुकदमा है जिसे उसी अदालत ने क्षेत्राधिकार के अभाव में वापस कर दिया है। बालक दास के अधिवक्ता का कहना है कि दान पात्रों में पुनः ताला लगाने के लिए अपने मुवक्किल की तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं।

**महंत कृष्णदास बयान**

महंत कृष्णदास का कहना है कि महंत पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। फैसला हमारे पक्ष में आया था। वीआईपी दर्शन शुल्क देश के सभी मंदिरों में यह व्यवस्था है। पनकी मंदिर में शुल्क सबसे कम है। पत्रकारों अधिकारियों प्रतिष्ठित लोगों वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को मुफ्त में वीआईपी दर्शन कराते हैं।

**एसीपी चकेरी की जांच पर क्या बोले !**

पुलिस है तिल को ताड़ बनाती है। पुलिस की नजर में हम गलत हैं, पुलिस सही है। यह तो विभाग विभाग का मामला होता है। जो किया ठीक है। हनुमान जी देखेंगे।

# मुठभेड़ में घायल हुआ बाइक लुटेरा, सर्राफा व्यापारी से लूट भी कबूली

» पुलिस ने मारी घेराबंदी, गोली चलाने पर जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल

» चांदी, नकदी व असलहा बरामद, फरार साथी की तलाश में लगी टीमें

**स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो**

कानपुर देहात। बीते दिन थाना भोगनीपुर क्षेत्र में बाइक चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी भोगनीपुर के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा पिलखनी मार्ग पर गश्त के दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वे भागने लगे।

पुलिस के पीछा करने पर खुद को घिरता देख आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया और मौके पर ही पकड़ा गया। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान रामकुमार पुत्र महावीर संखवार निवासी थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात के रूप में हुई। घायल रामकुमार को इलाज के लिए सीएचसी पुखरायां भेजा गया। पूछताछ में उसने 3 जुलाई को सर्राफा व्यापारी से की गई लूट की घटना स्वीकार की। उसके कब्जे से अवैध असलहा, लूटी गई चांदी व नगदी बरामद हुई।

फरार आरोपी हसन की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं पुखरायां सीएचसी पहुंचकर घायल आरोपी से पूछताछ की और घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

# बिजली बोर्ड लगाते समय युवक की करंट से मौत, गांव में मचा कोहराम

» हरियाणा से लौटे युवक की मौके पर ही गई जान, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

» परिजनों ने किया पोस्टमार्टम से इनकार, गांव में पसरा मातम का सन्नाटा

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के फत्तेपुर बकोठिया गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 35 वर्षीय विशाल यादव पुत्र कृष्ण पाल की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हाल ही में हरियाणा से अपने गांव लौटा था और घर के निर्माण कार्य में जुटा हुआ था। मंगलवार को वह खुद ही बिजली का बोर्ड लगा रहा था, तभी अचानक करंट की चपेट में आ गया।इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी मीरा बेसुध हो गई और चार मासूम बच्चों—दो बेटे व दो बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में मातम का माहौल है। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया, जिसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गईं।

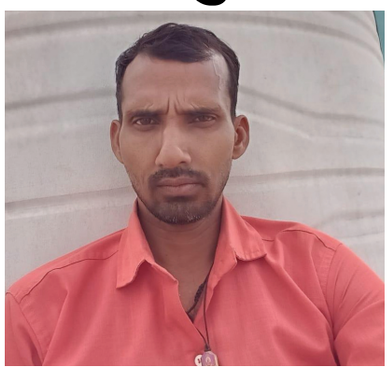

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

# राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाराबंकी में पौधरोपण महाअभियान का किया शुभारंभ

**» टीबी मरीजों को बांटी पोषण पोटली**

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

बाराबंकी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार सुबह बाराबंकी में तीन पेड़, एक उद्देश्य थीम पर आधारित पौधरोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने आर्मी कैंट परिसर में नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाए। इस अभियान को 'एक पेड़ मां के नाम' संकल्प से जोड़ा गया है, जिसमें स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, सेना के जवानों और समाजसेवी संगठनों ने भागीदारी की।

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि जिले में इस अभियान के तहत 58 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने की। डीएफओ आकाशदीप बधावन ने जानकारी दी कि पौधों की जिम्मेदारी विभागों को सौंपी गई है और अभियान लंबे समय तक सतत रूप से चलेगा।कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंगलवार से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं।

कैंट परिसर में मंच निर्माण, गड्ढे खोदने, साफ-सफाई और जनेस्मा रोड की मरम्मत के साथ नगर पालिका द्वारा बस स्टेशन से कैंट तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया।

इस दौरान राज्यपाल ने 101 टीबी मरीजों को पोषण पोटली भी वितरित की।

लाभार्थियों में तपस्या निषाद, बालेश्वर, लल्लन, मोहम्मद यावर और गौरव तिवारी समेत कई लोग शामिल रहे। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को लेकर समाज में जागरूकता जरूरी है। यह अभियान प्रकृति और मानवता दोनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है।

# ज़ैदपुर सीएचसी में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

ज़ैदपुर (बाराबंकी)।बुधवार को ज़ैदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) परिसर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सीएचसी अधीक्षक डॉ. जगदीश कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि यह अभियान शासन की मंशा और तय लक्ष्य के अनुरूप चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक पौधारोपण कर क्षेत्र को हरा-भरा बनाना है।

वृक्षारोपण के इस मौके पर चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ-साथ समाजसेवियों और नगर पंचायत कर्मियों ने भी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में डॉ. देवेश पटेल, डॉ. नजमुल सिद्दीकी, डॉ. शहिंदा खालिद, चीफ फर्मासिस्ट राकेश कुमार कनौजिया, एलटी दिनेश कुमार मिश्रा, श्रवण कुमार, रामगोपाल, संजय कुमार, राजकुमार, समाजसेवी कलीम अंसारी, नगर पंचायत लिपिक प्रदीप कुमार, सभासद अल्ताफ और मनीराम गौतम प्रमुख रूप से मौजूद रहे।सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और पौधों की देखरेख व संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली। कार्यक्रम के अंत में सीएचसी अधीक्षक ने सभी प्रतिभागियों का आभार जताया और जनभागीदारी से हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया।

# विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस पर ज़ैदपुर में निकाली गई बाइक रैली

**» पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य सलामुद्दीन लकी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल**

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

ज़ैदपुर (बाराबंकी)।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को ज़ैदपुर नगर इकाई की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य सलामुद्दीन लकी ने किया।

करीब दोपहर 1 बजे अली अकबर कटरा से शुरू हुई बाइक रैली, थाने चौराहा होते हुए पुनः अली अकबर कटरा पर समाप्त हुई। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाइक के साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ नगर भ्रमण किया। जागरूकता और संगठन के प्रति एकजुटता दिखाई दी।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सलामुद्दीन लकी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद 1949 से लगातार छात्रहितों की लड़ाई लड़ती आ रही है और आज भी यह संगठन विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में छात्रों की आवाज बनकर सक्रिय है।इस अवसर पर इस्तियाक अंसारी, अजय गुप्ता, सफीक, बंटी, अमन, अनीश अहमद, जावेद, सुहेल, वकील सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन की नीतियों पर चलने और छात्रहितों के लिए सतत सक्रिय रहने का संकल्प लिया।

# 50 से कम छात्र संख्या वाले सभी स्कूलों को किया जाएगा मर्ज

**इन स्कूलों में 89000 शिक्षक पढ़ाते हैं, यूपी सरकार का कहना है कि इन स्कूलों को समीप के बड़े स्कूलों में विलय करने से संसाधनों का और बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा**

**मामले में हरी झंडी दे दी है। सरकार अत्यधिक उत्साहित है और उसने सभी अधिकारियों को द्वितीय चरण में 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं।**

**मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया**

कानपुर/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 1.40 लाख सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में से लगभग 27000 स्कूलों में 50 या उससे कम छात्र हैं। इन स्कूलों में 89000 शिक्षक पढ़ाते हैं। यूपी सरकार का कहना है कि इन स्कूलों को समीप के बड़े स्कूलों में विलय करने से संसाधनों का और बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। इससे बेहतर बुनियादी ढांचा, पुस्तकालय और कक्षाओं की सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही यह नीति केंद्रीय सरकार के मुताबिक स्कूलों को पूर्ण रूप से कार्यात्मक बनाने और संसाधनों के इस्तेमाल के प्रस्ताव के अनुरूप है। हाल ही में हाई कोर्ट ने भी सरकार को स्कूल मर्जर

शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकारी स्कूलों की संख्या कम होने से गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच और भी मुश्किल हो जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल अक्सर शिक्षा का एकमात्र साधन होते हैं। यदि ये स्कूल बंद हो जायेंगे तो कई बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकते हैं, जिससे समाज में असमानता और बढ़ सकती है। आलोचकों का कहना है कि यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉपआउट दर को बढ़ा और बढ़ा देगी क्योंकि कई परिवारों के पास दूर के स्कूलों तक बच्चों को भेजने के लिए परिवहन या समय नहीं है। इसके अलावा, शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस नीति से 2 लाख से अधिक शिक्षक पदों की कटौती हो सकती है जिससे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और कम हो जाएंगे। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि जब स्कूलों की संख्या कम होगी तो अधिकांश शिक्षक सरप्लस होंगे मजबूरन में सरकार शिक्षकों को 50 वर्ष में ही सेवानिवृत्ति करने को मजबूर होगी।

# परिषदीय विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड की जगह अब व्हाइट व ग्रीन बोर्ड लगेंगे

**» बेसिक स्कूलों में 50 फीसद कंपोजिट ग्रांट से सुधरेगी व्यवस्था, बजट जारी**

**» स्कूल की दीवारों पर पेंट किया जाएगा ग्रांट का हिसाब-किताब**

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

लखनऊ/कानपुर। परिषदीय विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड की जगह अब व्हाइट व ग्रीन बोर्ड लेंगे। विद्यालयों को स्मार्ट बनाने के तहत चल रही कवायद, स्मार्ट क्लास रूम व पठन-पाठन के साथ ही अब व्हाइट व ग्रीन बोर्ड लगाए जाएंगे। वहीं विद्यालयों के लिए जारी कंपोजिट ग्रांट के व्यय आदि की जानकारी भी दीवारों पर पेंट की जाएगी ताकि सभी को इसके बारे में पता लग सके। परिषदीय स्कूलों के लिए सत्र 2025-26 के लिए कंपोजिट ग्रांट की 246 करोड़ (50 फीसदी) की राशि मंगलवार को जारी कर दी गई है।

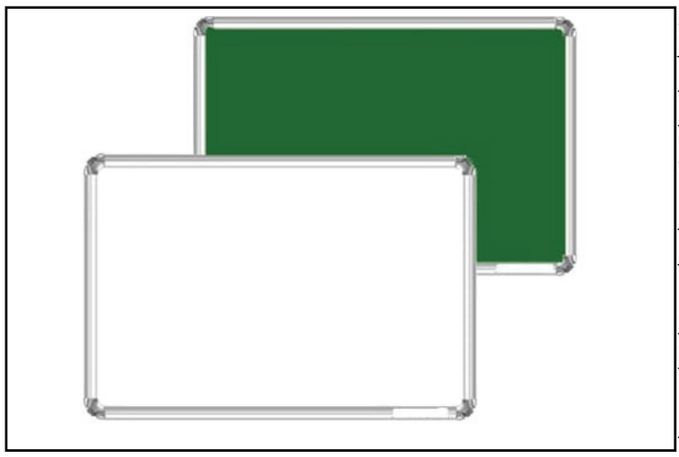

इसमें निर्देश दिया गया है कि सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में व्हाइट व ग्रीन बोर्ड लगाए जाएं। यह छात्रों के लिए ज्यादा उपयोगी व आंखों के लिए भी बेहतर होंगे। इस ग्रांट से विद्यालयों में प्रयोग के लिए दिए गए टैबलेट के लिए सिम व इंटरनेट में भी प्रयोग किया जा सकेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि कंपोजिट ग्रांट की 10 फीसदी राशि का प्रयोग विद्यालयों की सफाई पर अनिवार्यरूप में किया जाएगा। इससे जुड़ी सामग्री खरीदी जा सकेगी। इसके अलावा सभी विद्यालयों में आवश्यक दवाएं व फर्स्ट एड की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालयों में अग्निशमन यंत्र की भी व्यवस्था की जाए। विद्यालय के एलईडी, ट्यूबलाइट, पंखे आदि को भी ठीक कराया जाए।

**परिषदीय विद्यालयों में अब सुधरेगी व्यवस्था-**

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और संविलियन विद्यालयों में बेहतर व्यवस्था के लिए शासन की ओर से 50 फीसद कंपोजिट ग्रांट जारी कर दी गई है जिसके तहत कानपुर देहात को 2.94 करोड़ रूपए की धनराशि दी गई है। कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि अनिवार्य रूप से स्वच्छता अभियान / कार्यक्रम पर व्यय हेतु आरक्षित है जो विद्यालय भवन, परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय में आवश्यकतानुसार स्वच्छता सामग्री, यथा- टॉयलेट क्लीनर, फिनायल, साबुन, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेलकटर, हैण्डवॉश इत्यादि प्रत्येक दशा में वर्ष पर्यन्त उपलब्ध रहे। शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इण्टरनेट की सुविधा (वित्तीय वर्ष 2025-26) हेतु रिचार्ज कराए जाने वाले बिल का भुगतान स्वीकृति के अनुरूप जनपद स्तर से किया जाये। उक्त सम्बन्ध में सूचना संकलन एवं पत्रावली व्यवहृत करने का कार्य जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा किया जायेगा। निपुण भारत के लोगो की पेन्टिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाये जो जनसामान्य हेतु प्रथम दृष्ट्या दृश्यमान हो। पेन्टिंग की माप आयताकार (45 सेमी चौड़ा एवं 60 सेमी ऊँचाई) के आकार में होगी। विद्यालय के ऐसे शौचालय / मूत्रालय जो छोटी-छोटी मरम्मत / छोटे-छोटे आवश्यक कार्य यथा- शौचालय शीट/यूरिनल पॉट में टूट-फूट आदि के कारण अक्रियाशील हैं उनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशील करा लिया जाये। यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाये।

## नामांकन के आधार पर मिलेगा पैसा-

**1 से 15 नामांकन पर 12500 रुपए स्कूल को मिलेगा जिसमें 1250 रुपए स्वच्छता के होंगे।**

**16 से 100 नामांकन पर 25000 रुपए मिलेगा जिसमें 2500 रुपए स्वच्छता के होंगे।**

**101 से 250 नामांकन पर 50 हजार मिलेंगे जिसमें 5 हजार स्वच्छता मद के होंगे।**

**251 से 1000 तक नामांकन रखने पर 75 हजार मिलेंगे जिसमें स्वच्छता मद के 7500 रुपए दिए जाएंगे।**

**1000 से अधिक नामांकन पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जिसमें स्वच्छता के लिए 10 हजार रुपए होंगे।**

# अयोध्या नगर निगम की नाकामी से रामपथ बना तालाब

» जलवानपुरा में लोगो के घरों में घुसा 3 से 4 फ़ीट पानी

» नगर निगम के जिम्मेदारों के मोबाइल स्विच ऑफ

» जनता पूछ रही है साहब जी करोड़ों का बजट आखिर बहा कहां?

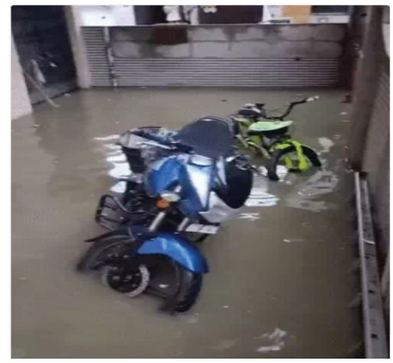

लोग बाल्टी से पानी निकालते रहे, जबकि जिम्मेदारों के मोबाइल स्विच ऑफ मिले।

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

अयोध्या। भोर की पहली बारिश ने अयोध्या नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की 'स्मार्ट प्लानिंग' को पूरी तरह से धो डाला। चार घंटे की मूसलधार बारिश के बाद शहर की गलियों में नदियाँ बहने लगीं और रामपथ, जो विश्वभर के श्रद्धालुओं के लिए भव्यता का प्रतीक माना जाता है, वह भीषण जलभराव से बदहाल हो उठा। जलवानपुरा मोहल्ला एक बार फिर नगर निगम की नाकामी का चेहरा बन गया। यहां लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी घुस गया है। लगभग 10 हजार लोग प्रभावित हुए, लेकिन नगर निगम की ओर से न तो पम्पिंग सेट पहुंचे, न ही राहत की कोई कार्रवाई दिखी। स्थानीय

रामपथ बना राम-नदी

हनुमानगढ़ी तिराहा से श्रीराम अस्पताल तक रामपथ पर इतना पानी जमा हो गया कि लोग जान जोखिम में डालकर निकलते नजर आए। गांधी आश्रम, पंचमहला चौराहा, दिव्यकला मार्ग और उर्दू बाजार इलाके में कीचड़ और जलभराव से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन मार्ग पर भी यात्रियों को घुटनों तक पानी पार करके स्टेशन पहुंचना पड़ा। वहीं, नागेश्वरनाथ मंदिर के सामने पानी और गंदगी के चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित रही। 'डबल इंजन' की सरकार में आस्था की नगरी को देखने आए लोग गड्ढों और गंदगी में उलझे दिखे।स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट सिर्फ छलावा

हैरानी की बात यह है कि करोड़ों की लागत से स्मार्ट सिटी के तहत जो ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम बनाया गया, वह पहली ही बारिश में बैठ गया। सवाल उठता है – क्या स्मार्ट सिटी की यह हालत भी कोई स्मार्ट रणनीति का हिस्सा है? नगर निगम के अभियंता और अफसर आखिर किसकी जेबें भर रहे हैं और किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा?

हालांकि इस बारिश ने सरयू तट की खूबसूरती को और निखार दिया है। सरयू की लहरों से उठती ठंडी हवा श्रद्धालुओं को सुकून दे रही है। स्नान घाटों पर चहल-पहल बढ़ी है। किसानों की भी चिर प्रतीक्षित आस पूरी हुई है धान की रोपाई शुरू हो गई है और खेतों में रौनक लौट आई है। रामनगरी की सड़कों पर अगर जलभराव है, तो यह केवल वर्षा की मार नहीं, बल्कि वर्षों से जमा हुई भ्रष्टाचार की दलदल का परिणाम है। सवाल यह है करोड़ों का बजट आखिर बहा कहां?

# 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से गूंज उठी रामनगरी

» सीएम योगी ने रोपे बरगद-नीम-पीपल

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अयोध्या के रामपुर हलवारा स्थित त्रिवेणी वाटिका में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बरगद, नीम और पीपल के पौधे रोपकर इन्हें भगवान श्रीराम, धरती माता और जन्मदायिनी माता को समर्पित किया।

मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 204 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 75 जीवित हैं।

इससे 5 लाख एकड़ वन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है। योगी ने कहा कि हीटवेव को ग्रीनवेव में बदलने का प्रयास न सिर्फ पर्यावरण रक्षा में सहायक है, बल्कि किसानों को कार्बन क्रेडिट के रूप में आर्थिक लाभ भी दे रहा है।

कार्यक्रम में अयोध्या के कायाकल्प, सोलर सिटी विकास और जलवायु परिवर्तन पर भी सीएम ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को विश्वपटल पर गौरव दिलाने का यह अभियान संकल्प और समर्पण दोनों है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।

# यूपी में पहली बार जारी हुआ महिला आर्थिक सशक्तीकरण सूचकांक

## लखनऊ-वाराणसी टॉप पर, सीएम योगी की अध्यक्षता में जारी हुआ इंडेक्स

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**लखनऊ।** प्रदेश में महिलाओं को सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है? किन जिलों में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और कहां अब भी हालात सुधरने बाकी हैं? इन सवालों का जवाब अब एक आंकड़े के रूप में सामने है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश का पहला ''महिला आर्थिक सशक्तीकरण सूचकांक'' यानी डब्लूईई इंडेक्स जारी किया गया। इसमें लखनऊ, कानपुर नगर और वाराणसी जैसे जिले टाप पर हैं, जबकि श्रावस्ती, महोबा, बलरामपुर, संभल और सिद्धार्थनगर जैसे जिले महिला कल्याण के मामले में पीछे रह गए हैं।

यह सूचकांक योजना विभाग ने उदयती फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया है। इसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ महिलाओं तक किस हद तक पहुंच रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।

इंडेक्स के तहत उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका, सुरक्षा और परिवहन जैसी पांच प्रमुख श्रेणियों के आधार पर प्रदेश के सभी 75 जिलों का विश्लेषण किया गया। जहां लखनऊ, कानपुर नगर और वाराणसी ने महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

वहीं श्रावस्ती, महोबा, बलरामपुर, संभल और सिद्धार्थनगर जिलों को इस दिशा में खास मेहनत करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सूचकांक केवल एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी का प्रभावी उपकरण बने। उन्होंने निर्देश दिया कि सूचकांक को मुख्यमंत्री नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाए और सभी विभाग इसे अपने नीति निर्माण का हिस्सा बनाएं।

जिलों को निर्देश है कि वे अपने-अपने जिले के इंडेक्स स्कोर के आधार पर महिला सशक्तीकरण की स्थानीय रणनीति तैयार करें। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी मार्जिन मनी योजना के तहत महिलाओं को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही होमगार्ड और शिक्षक भर्तियों में भी महिलाओं को पुलिस भर्ती की तरह वरीयता देने का सुझाव दिया।

महिलाओं की तकनीकी और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में भागीदारी बढ़ाने, फिर नामांकन इकाइयों की स्थापना, और सार्वजनिक परिवहन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस प्रयास किए जाएंगे। सभी विभागों से अपील की कि सूचकांक को केवल आंकड़ों की रिपोर्ट न समझें, बल्कि इसे ठोस कार्ययोजना का आधार बनाकर महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाया जाए।

**खुलासे पर हंगामा**

## मौत के बाद लाश का इलाज करते रहे डॉक्टर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**पीलीभीत।** पीलीभीत में निजी अस्पताल के आईसीयू में भतीज घायल युवक की मौत हो गई। उसके परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद भी डॉक्टर उसका इलाज करते रहे। इलाज के नाम पर तीन लाख रुपये वसूल लिए। मंगलवार को रेफर करने के लिए मरीज को बाहर निकाला तो उसकी मौत हो चुकी थी।

माधोटांडा मार्ग पर एक अस्पताल है। पूरनपुर क्षेत्र के चांट फिरोजपुर निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया कि चार दिन पूर्व उसके छोटे भाई विष्णु पुत्र प्रेमराज सिरसा चौराहे के पास हादसे में घायल हो गए थे। भाई को पूरनपुर सीएचसी के बाद शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। राजेंद्र ने बताया कि चिकित्सक को भर्ती करने के लिए 30 हजार रुपये दिए। कुछ घंटे बाद ऑपरेशन के नाम पर एक लाख रुपये और लिए गए। चार दिन में करीब तीन लाख रुपये जमा करा लिए। इस बीच परिजनों को एक बार भी मरीज को देखने नहीं दिया गया। आईसीयू गेट के पास जाने पर हटा दिया गया। मंगलवार शाम बरेली रेफर करने की बात कहकर मरीज को बाहर निकाला तो उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि मृतक के शरीर को देखने पर उसकी मौत करीब तीन दिन पूर्व होने की बात सामने आ रही है।

**सनसनीखेज**

**बीएचयू आईआईटी के हॉस्टल में रहने करीब 4 दर्जन से ज्यादा छात्र पहुंचे थाने**

# वॉशरूम में कैमरा, साथी ही छात्रों का बना रहा था प्राइवेट वीडियो

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**वाराणसी।** देश की प्रतिष्ठित बीएचयू आईआईटी संस्थान से एक बेहद चौंकाने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई है। आईआईटी के पीसी रे हॉस्टल में रहने वाले एमटेक के करीब 4 दर्जन से ज्यादा छात्र अपने ही साथी छात्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए लंका थाने पहुंच गए।

दरअसल, इन छात्रों ने अपने ही एक साथी छात्र पर वॉशरूम में चोरी से वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। छात्रों के अनुसार, आरोपी के मोबाइल में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों के प्राइवेट वीडियो मिले हैं और आरोपी ने उन वीडियो को कई जगह शेयर करने की बात भी कबूल कर ली है।

**साथी छात्र चुपके से बनता था मोबाइल से वीडियो :** मंगलवार की देर रात लंका थाने पर करीब 50 की संख्या में छात्र पहुंचे। इन छात्रों ने तीन पन्ने की लिखित शिकायत लंका थाने में दी। शिकायत के अनुसार, पीसी रे हॉस्टल में रहने वाले ही एक साथी छात्र ने सैकड़ों छात्रों का वॉशरूम में नहाते समय का वीडियो बनाया और उसे कई जगह सर्कुलेट किया। रविवार की रात एक छात्र जब नहाने के लिए वॉशरूम में गया तो उसे वीडियो बनाने का शक हुआ। छात्र ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया । जिसके बाद अन्य छात्रों ने वार्डन और प्रॉक्टोरियल टीम के सामने उस छात्र से कड़ाई से पूछताछ की।

छात्रों को आरोपी छात्र के मोबाइल में करीब आधा दर्जन से ज्यादा कई छात्रों के प्राइवेट वीडियो भी मिले। जब कड़ाई से पूछा गया तो छात्र ने कबूल किया कि वो कई महीनों से वीडियो बना रहा था और उसने वीडियो कई जगह शेयर भी किया है।

**छात्र आईआईटी प्रशासन से भी है नाराज :** शिकायत करने आए एमटेक के छात्र हिमांशु ने बताया कि भविष्य में हम सभी लोग प्लेसमेंट के बाद नौकरी करेंगे। कुछ समय बाद हम लोग समाज में अच्छी जगहों पर जाएंगे क्या पता उस समय इन वीडियो का इस्तेमाल कर हमें ब्लैकमेल किया जाए। इसी डर से हम लोगों ने आईआईटी प्रशासन से स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग बीते दो दिनों से कर रहे थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से हमें मजबूर होकर थाने में कम्प्लेन करने आना पड़ा।